

## SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)



स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में जाति और चुनावी राजनीति

अभिमन्यु कुमार प्रजापति, शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग,  
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत

### ORIGINAL ARTICLE



#### Corresponding Author

अभिमन्यु कुमार प्रजापति, शोधार्थी,  
राजनीतिक विज्ञान विभाग,  
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,  
झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/10/2020

Revised on : -----

Accepted on : 23/10/2020

Plagiarism : 02% on 16/10/2020



Plagiarism Checker X Originality Report  
Similarity Found: 2%

Date: Friday, October 16, 2020

Statistics: 38 words Plagiarized / 1739 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

PLFkkuh; fudk; pquko ds lanHkZ esa tkfr vkSj pqukoh jktuhfrP 'kks/k lkjka'k Hkkjr esa fo;eku tkfrokn u; u dsoy ;gk; fd vklfkZd] Ikekfd] lkad c'frd] /kkfleZd izo 'Rrjksa dks gha izHkkfor fd;k vflrq jktuhfr dks Hkh iw.kZ : ls izHkkfor fd;k gSA tkfr ds vk/kkj ij HksnHkkko Hkkjr esa Lok/khurk izkflrs ls iwoZ Hkh Fkk fdarq Lora=rk izkflrs ds i'pk; izkra= dh LFkkiuk ij Lke>k x;k fd tkfrxr Hksn feV tk,xk fdarq ,slk ugha gqvkA jktuhfrd LakLFkk,ij Hkh blls izHkkfor gq, fcuk ugha jg lhd ifj,kke Lo:i tkfr d; jktuhfrdjk.

### शोध सार

भारत में विद्यमान जातिवाद ने न केवल यहाँ कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृत्तियों को हीं प्रभावित किया अपितु राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जाति के आधार पर भेदभाव भारत में स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भी था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रजातंत्र की स्थापना पर समझा गया कि जातिगत भेद मिट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक संस्थाएँ भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी परिणाम स्वरूप जाति का राजनीतिकरण हो गया। भारत की राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केन्द्र हीं नहीं राज्य स्तरीय राजनीति भी जातिवाद से प्रभावित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक बात है क्योंकि राष्ट्रीय एकता एवं विकास मार्ग अवरुद्ध है।

### मुख्य शब्द

स्थानीय निकाय चुनाव जाति और चुनावी राजनीति।

भारतीय संविधान में जाति निरपेक्ष राजनीति व्यवस्था कायम की है तथापि देश की राजनीति सामाजिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जो जातिवाद से प्रभावित ना हो। आज भारतीय राजनीति और जाति व्यवस्था में बड़ा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है, जिसे हम राजनीतिक भाषा में जातिवाद नाम देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो आज की राजनीति जाति का राजनीतिकरण हो गया है। भारतीय समाज मुख्य रूप से ग्रामीण समाज है, जिसका प्रमुख आधार जाति व्यवस्था है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रांरभ होने के पश्चात् अवधारणा विकसित हुई कि, यहाँ की पारम्परिक संस्था जाति का अंत हो जाएगा, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीति के स्थानीय निकाय चुनाव में जाति का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। पंचायती राज स्थानीय

निकाय संस्था के रूप में पंचायती राज पद्धति का हमारे देश में एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन में भी पंचायती राज पद्धति का प्रचलन के तत्व मौजुद थे, तब उसे पंचायती राज पद्धति के नाम से नहीं जाना जाता था। भारत जैसे विशाल देश में स्थानीय पंचायती राज प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है, इसकी जानकारी हमें प्रारंभिक साहित्य जैसे—वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद् व जातक कथाओं में देखने को मिलती है। उस समय जाति प्रथा और सती प्रथा सबसे अधिक पायी जाती थी। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागु करने के लिए एक समिति बनी जिसे “बलवंतराय मेहता समिति” नाम दिया गया जो आज हमारे देश में कई राज्यों में लागू है।

स्थानीय चुनाव में जाति भारतीय समाज की संरचना का केंद्र आधार रहा है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में जाति की संरचना बेहद जटिल है। आजादी के बाद जो लोकतंत्र के रूप में भारत राष्ट्र बना उसमें जातियों की भुमिका को नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं जातियों के ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय सत्ता संरचना खड़ी है। और स्थानीय व केन्द्रीय चुनाव में इसका स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। चुनावी राजनीति में वह जिस में जन्म लेता था, उसी के अनुसार उसका पेशा निर्धारित हो जाता था। प्रारंभिक दौर के बारे में कहा जाता है कि पेशा के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था दृढ़ हो जाने के बाद रिथिति उल्टी हो गई, जाति के आधार पर पेशा तय होने लगा। भारतीय चुनाव प्रणाली में कोई भी दल ऐसा नहीं है, जो जाति को चुनाव प्रक्रिया से अलग करने का दावा करे। चाहे कोई भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल हो जाति उसकी राजनीति का केन्द्रीय तत्व होता है। चुनावी राजनीति में जातिगत आधार का बढ़ता महत्व और चुनाव प्रक्रिया में जातियों को ध्रुवीकरण बढ़ता गया है। देश की आजादी और फिर यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के साथ हीं जातियों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया था। भेदभाव पूर्ण जाति व्यवस्था को नए भारत के निर्माताओं ने एक बड़े अवरोध के रूप में देखा था। लेकिन व्यवहार में हुआ कि जातियों को समाप्त की जितनी भी कोशिश की गई, जातियों का ध्रुवीकरण बढ़ता गया। इस ध्रुवीकरण के कारण भारत में जातिवाद तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन हुए। मसलन सर्वांगीजातियों के वर्चस्व पर जो आधारित भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसमें पिछड़े और दलित वर्गों का प्रवेश बढ़ने लगा और इस प्रकार राजनीति और चुनाव में सर्वांगीजातियों के समानान्तर राजनीति शक्ति का उदय हुआ।

भारतीय राजनीति में चाहे वह केन्द्रीय या स्थानीय निकाय चुनाव हो, उस में जातियों की संरचना और स्वरूप को पार्टियों ने अपने ढंग से अपनी राजनीति का औजार बनाया। और परिणाम स्वरूप लंबे समय तक इस ध्रुवीकरण का अपने हित में अपने तरीके से उपयोग किया, और आजादी के बाद तक इससे उसने चुनावी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखा। जातियों की चुनावी ध्रुवीकरण का अपने हित में उपयोग करने के लिए पार्टियों ने दोहरी रणनीति अपनाई। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीतियों को उसने राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में पेश किया। जबकि क्षेत्रीय स्तर पर निचले दर्जे वाली भूस्वामी किसान जातियों के साथ रुझान प्रदर्शित किया। ये किसान जातियां पारंपरिक रूप से भले हीं निम्न दर्जे वाली थीं, लेकिन वास्तव में संख्यात्मक आधार पर सामाजिक रूप से मजबूत और तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रही जातियां थीं। जिसको स्थानीय निकाय चुनाव में जाति को अपना आधार बनाया।

भारत के परिपेक्ष में लगभग सभी राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में देखा जाए, तो सभी राज्य में जाति आधारित राजनीति होने लगी है, विशेषकर बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में जातिवाद का प्रभाव बहुत अधिक है। ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव के नजदीक आ जाने से जाति ज्यादा प्रभाव में आने लगती है, भारत के स्थानीय चुनाव में जातिय राजनीति में बहुरंगी देखी जा सकती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तबसे ही पंचायती राज व्यवस्था लागु नहीं हुई, बल्कि यह देश स्वतंत्र नहीं था तबसे हीं भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी, और उस समय भी जाति प्रथा हमारे देश में सबसे ज्यादा दिखाई देता था। वर्तमान में भारत में स्थानीय चुनाव के लिए जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में राज्यों की राजनीति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जैसे भारत में जाति

पर राजनीति व्यवस्था का प्रभाव एक लंबे ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है, किंतु आधुनिक भारत में स्थानीय निकाय चुनाव में राज्यों में यह प्रभाव बहुत उन्मुख रूप से दिखाई पड़ता है। डॉ० रजनी कोठारी के शब्दों में "राजनीति में जातिवाद और जाति का राजनीतिकरण दोनों प्रविधियाँ एक साथ दिखाई पड़ती हैं।" बलवंतराय मेहता समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था में जातीय भूमिका को स्वीकारा है। उनका मानना था कि जाति भी पंचायती राज व्यवस्था में आम भूमिका निभाती है। जातीय समीकरण के आधार पर ही प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होती है। बलवंतराय मेहता की यह बात से हमें यह प्रतीत होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जातियां अहम भूमिका निभाती हैं।

वर्तमान की चुनावी राजनीति को इस प्रकार आयाम देखा जा सकता है, कि स्थानीय निकाय चुनाव में जातिगत अवधारणाएँ आज जातियों ने नवीन संगठनात्मक स्वरूप धारण कर लिया है। इस प्रकार अब विभिन्न स्तरों पर जाति संघ कार्य कर रहे हैं, जैसे— विश्वविद्यालयों, हॉस्टलों, क्लब, सरकारी कार्यालय आदि में देखा जा सकता है। जाति सम्मेलन विस्तृत आधार वाले हो गए हैं, और जाति महास्वयंभू का उदय हुआ है। इसका प्रभाव स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। जातियों ने गुट के आधार पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यह न केवल राजनीतिक समूहों को विभाजित करते हैं, बल्कि सामाजिक समूहों को भी। स्थानीय चुनाव में जातिवाद और संप्रदायवाद तथा इसके साथ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति ने विभिन्न जातियों में संदेह और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। स्थानीय निकाय चुनाव में जाति में उच्च पदासीन व्यक्ति नियुक्तियों और प्रोन्नति में अपनी जाति या उपजाति के सदस्यों को वरीयता देते हैं। वर्तमान के चुनावी राजनीति में यह काफी हद तक देखा जा सकता है, चुनावी राजनीति में जाति की बढ़ती भूमिका हमारे देश के लिए काफी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जाति और राजनीति के बीच संबंध का स्तर पर विश्लेषण किया गया है, एक जाति राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है और दूसरा राजनीति किस प्रकार जाति को प्रभावित करती है। स्थानीय निकाय चुनाव में चुनावी राजनीति के जाति के संस्थागत रूप और आधुनिक संस्थाओं के विविध रूपों के बीच अन्य क्रिया चयनात्मक थी। संभवतः इसी कारण हमारे देश के अभिजन बुद्धिजीवी इस भ्रम के शिकार रहे की जाति लुप्त हो जाएगी और जाति विहिन समाज की रचना संभव होगी। वास्तव में जाति एक संस्था है, और समाज की कोई संस्था लुप्त नहीं होती उसका स्वरूप भले हीं बदल जाए। इसी प्रकार जो बुद्धिजीवी इस बात से भिन्न होते हैं कि राजनीति में जातिवाद बढ़ रहा है, वे दरअसल भावुक बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि व्यवहार में ऐसे राजनीति का समाज में कोई आधार नहीं हो सकता। जाति भारतीय समाज का सच्चाई है और इस सच्चाई से मुँह मोड़ना यथार्थ से मुँह मोड़ना है। रजनी कोठारी के अनुसार जिसे हम राजनीति में जातिवाद कहते हैं वह वास्तव में जातियों का राजनीतिकरण है।

## निष्कर्ष

स्थानीय निकाय चुनाव में हमारे देश में राजनीति की अवधारणा व्यापक विषय के रूप में परिणत हो गया है, उपरोक्त विचारों के आधार पर हमारे देश की जातीय राजनीति में स्थानीय निकाय चुनाव में कोई भी दल ऐसा नहीं है, जो जाति की चुनाव प्रक्रिया से अलग करने का दावा करता है। स्थानीय या केन्द्रीय चुनाव में जाति राजनीति के माध्यम से देश की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। स्थानीय केन्द्रीय चुनाव में स्थानीय राजनीति के आधार पर जाति आधारित चुनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, यह लोकतंत्र के चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो जाति एक संस्था है, और समाज की कोई संस्था समाप्त नहीं हो सकती है। वर्तमान में जाति के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, यह एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, स्थानीय निकाय चुनाव में जाति और चुनावी राजनीति लगातार बढ़ता जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए एक खतरा का स्वरूप दिखाई पड़ता है, और कहीं न कहीं जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो रही है। यह एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। जाति का राजनीतिकरण

‘आधुनिकीकरण’ के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जाति को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक–साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता का निर्माण करने हेतु आधार नहीं बनाया जा सकता। आज आवश्यकता इस बात कि है कि हमारे देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक दलों के नेता इस संदर्भ में ईमानदारी के साथ सोचें और इस समस्या एवं इससे उत्पन्न अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु गंभीरता पूर्वक प्रयास करें।

## संदर्भ सूची

1. शर्मा, विरेन्द्र एवं शर्मा रिचा, “पंचायती राज”, युनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली 110002।
2. वीर, गौतम, “पंचायती राज व्यवस्था”, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली—110002।
3. त्रिवेदी, आर.एन., “भारतीय राजनीतिक व्यवस्था”, जयपुर।
4. कोठारी, रजनी, “भारत में राजनीति”।
5. भारत में ग्रामीण विकास, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
6. माहेश्वरी, एस.आर., “भारत में स्थानीय शासन”।
7. सिंह, बी.पी., “पंचायती राज”, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

\*\*\*\*\*

